

कमिंस में छुट्टी लेने पर अब नहीं कटेगा टीबीडब्ल्यूएस का पैसा, एलटीए के भुगतान के लिए मिलेंगे तीन विकल्प

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

नये श्रम कानून के अनुपालन में टाटा कमिंस प्रबंधन ने कर्मचारियों के वेज स्ट्रक्चर (वेतन संरचना) में बदलाव किया है. नये कानून के तहत अब कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा उनके बेसिक और डीए (महंगाई भत्ता) में शामिल होगा. इस बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों को मई में मिलने वाले अप्रैल माह के वेतन में दिखाई देगा. इस पहल से न केवल वर्तमान वेतन सुधरेगा, बल्कि भविष्य में मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि में भी बड़ा इजाफा होगा. इसकी जानकारी टाटा कमिंस की मान्यता प्राप्त टीसी कर्मचारी यूनियन के महामंत्री आशीष अनुपम ने दी.



> नया श्रम कानून प्रभावी होने के बाद कमिंस पहली कंपनी है. जिसने वेज स्ट्रक्चर में बदलाव किया है. इसका लाभ सभी कर्मचारियों को उनके वेतन में मिलेगा और भविष्य में मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि काफी बेहतर हो जायेगी.
> **आशीष अनुपम,** महामंत्री, टीसी कर्मचारी यूनियन

शिक्षा भत्ता अब वेतन का हिस्सा, ग्रेच्युटी में मिलेगा लाभ : महामंत्री आशीष अनुपम ने बताया कि नयी व्यवस्था के तहत कमिंस कर्मचारियों को मिलने वाले 200 रुपये के शिक्षा भत्ते को अब उनके मूल वेतन का हिस्सा बना दिया गया है. इसके अलावा जो फिक्स एलाउंस थे. उन्हें परिवहन भत्ते के साथ एकीकृत किया गया है. नये स्ट्रक्चर में सप्लीमेंट्री एलाउंस (10,500 रुपये), टीम बेस्ड वर्क्स सिस्टम (टीबीडब्ल्यूएस- 1050 रुपये), गुड सर्विस एलाउंस, ट्रांसपोर्ट एलाउंस और स्पेशल एलाउंस को भी वेतन के मुख्य मदों से जोड़ दिया गया है. यह व्यवस्था जमशेदपुर प्लांट सहित कमिंस इंडिया लिमिटेड और फल्टन प्लांट में एक साथ लागू कर दी गयी है.

एलटीए : हर माह, एक साल या दो साल में ले सकेंगे कर्मी : लीव ट्रैवल्स एलाउंस (एलटीए) को लेकर टाटा कमिंस कर्मचारी यूनियन ने बड़ी सफलता हासिल की है. अब कर्मचारी हर माह, वर्ष में एक बार और दो वर्ष में एक बार भुगतान ले सकते है. वर्तमान में एसपीसी ग्रेड के कर्मचारियों को अधिकतम 45,000 रुपये और जूनियर एसोसिएट को 39,000 रुपये एलटीए के रूप में मिलते हैं. इसका लाभ जमशेदपुर स्थित टाटा कमिंस प्लांट में कार्यरत 764 कर्मचारियों को मिलेगा.

कैजुअल या सिक लीव लेने पर वेतन में नहीं होगी कटौती : कैजुअल या सिक लीव लेने पर वेतन में कटौती नहीं होगी. पहले प्रतिदिन की छुट्टी पर टीबीडब्ल्यूएस मद से 35 रुपये काट लिए जाते थे. जिसे अब फिक्स कर दिया गया है. गुड सर्विस एलाउंस के तहत पहले 240 दिन से कम उपस्थिति या चेतावनी पत्र (वार्निंग लेटर) मिलने पर लाभ रोक दिया जाता था. साल भर नहीं मिलता था. अब नयी व्यवस्था में कर्मचारियों को 350 रुपये प्रतिमाह का फिक्स एलाउंस मिलना तय हुआ है.

हाइकोर्ट ने अनुपालन के लिए दिया एक सप्ताह का समय

□ टेल्को वर्कर्स यूनियन मामला

जमशेदपुर. झारखंड उच्च न्यायालय ने टेल्को वर्कर्स यूनियन से जुड़े विवाद में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पक्ष को अदालती निर्देशों के अनुपालन के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है. न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने 19 मार्च 2026 के पूर्व आदेश का पालन करने के लिए समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आदेश के पैराग्राफ आठ में उल्लेखित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाये. अदालत ने इस मामले को 30 अप्रैल 2026 को सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट (पूरक कार्यसूची) में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. इस दिन इस पर अगली सुनवाई होगी.

इंटक की मान्यता बहाल, शासकीय बैठकों में अब शामिल हो सकेंगे संगठन के लोग

जमशेदपुर. देश की प्रमुख श्रमिक संगठन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) को बड़ी कानूनी राहत मिली है. दिल्ली हाइकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने वर्ष 2017 में लगाये गये प्रतिबंध को अप्रासंगिक बताते हुए संगठन की मान्यता बहाल कर दी है. इस निर्णय के बाद अब इंटक के लिए शासकीय बैठकों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व का मार्ग पुनः प्रशस्त हो गया है. न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि वर्ष 2017 में लगाया गया प्रतिबंध वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता है. साथ ही केंद्र सरकार को निर्देशित किया गया है कि वह 8 सप्ताह के भीतर उस आदेश की समीक्षा करे. इस फैसले के बाद श्रमिक संगठनों के बीच इंटक की सक्रिय भूमिका एक बार फिर सुनिश्चित मानी जा रही है. मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) की जांच में डॉ जी संजीव रेड्डी के नेतृत्व वाली इंटक को ही वैध पाया गया, जबकि अन्य दावों को निरस्त कर दिया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला केवल एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि देशभर के श्रमिकों के प्रतिनिधित्व और अधिकारों की पुनर्स्थापना का प्रतीक है. लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता के बाद अब इंटक को नई मजबूती मिली है.

बैंक ऑफ़ इंडिया, आस्ति वसूली विभाग (एआरडी)

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

जमशेदपुर क्षेत्र, द्वितीय तल, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, मेन रोड
बिष्टुपुर, जमशेदपुर - 831001
ई-मेल : ARD.Jamshedpur@bankofindia.bank.in

बैंक के पक्ष में जब्त वाहनों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

जन साधारण को सामान्यत: एवं ऋणियों और जमानतदारों को विशेष तौर पर सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जब्त किये गये वाहनों की बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा **" जहाँ है, जिस हालत में है और जो है के आधार पर "** निम्नवर्णित ऋणियों और जमानतदारों से बैंक ऑफ इंडिया के बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 26.05.2026** को होगी। आरक्षित मूल्य और ईएमडी राशि का विवरण नीचे तालिका में है।

शाखा का नाम	ऋणकर्ता का नाम	वाहनों का विवरण			आरक्षित मूल्य (रूपये में)	अग्रधन जमा राशि (रूपये में)
		रजि. नं.	मॉडल	वर्ष		
सोनारी शाखा	**कामिनी कुमारी**	JH05DG-2118	MAHINDRA BOLERO B4 BS VI	JULY. 2022	6,00,000/-	60,000/-

नीलामी ऑनलाइन पोर्टल www.baanknet.in के माध्यम से होगी। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, www.baanknet.in बोलीदाता पंजीकरण विकल्प पर जाएँ।

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 25.05.2026 शाम 04:00 बजे तक।
ई-नीलामी की तिथि और समय : 26.05.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ
वाहनों के निरीक्षण की तिथि और समय : 25.05.2025 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक (प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें)
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: **श्री सत्य प्रकाश, मोबाईल नंबर 9973066728 (शाखा प्रबंधक, सोनारी शाखा)** या **श्री बिमल प्रसाद सिंह (मुख्य प्रबंधक ARD जमशेदपुर) – मोबाईल नंबर 8451805554.**
बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.bankofindia.bank.in पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें.

दिनांक : 24.04.2026, स्थान : जमशेदपुर — नोट: त्रुटि / विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा। — ह०/– प्राधिकृत अधिकारी

बिहार सरकार

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी (गया)
(मद्यनिषेध एवं उत्पाद न्यायालय)

आम सूचना

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध वं उत्पाद (संसोधन) नियमावली 2022 के नियम 12 (क) के तहत जप्त वाहनों से संबंधित मामलों की सुनवाई अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचारधीन है। जिसमें वाहन मालिको को शस्ति के आधार पर मुक्त करने हेतु समय दिया जाना आवश्यक है। निम्नांकित वाहन मालिको को डाक द्वारा सूचना भी भेजी गई परन्तु अनुपस्थित रहे।

वर्णित परिस्थिति में बिहार मद्यनिशेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (3) के तहत आम सूचना प्रकाशित कर जप्त वाहन के मालिको को सूचित किया जाता है कि यदि निम्नांकित जप्त वाहनों के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था का हीत निहीत हो तो वे इस आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वंय या अधिवक्ता के माध्यम से जप्त वाहन के वैध कागजात सहित उपस्थित होकर विहित प्रपत्र IV में आवेदन समर्पित करते हुये उत्पाद एवं मद्यनिषेध बिहार पटना द्वारा निर्धारित शास्ति का भुगतान कर जप्त वाहन को मुक्त करालें। यदि निर्धारित अवधि तक संबंधित व्यक्ति/संस्था द्वारा अपनी उपस्थिति नही दी जाती है तथा विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित नहीं किया जाता है तो इस जप्त वाहनों को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (3) के तहत राज्यसात का यथोचित आदेश पारित कर दिया जाएगा।

वाहन (झारखण्ड) का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	उत्पाद/थाना कांड सं०	उत्पाद अधिग्रहण वाद सं०	वाहन का प्रकार	वाहन का 1. रजिस्ट्रेशन नं० 2. ईंजन नम्बर 3. चेचिस नम्बर	जप्त वाहनों के मालिक का नाम व पता
1	2	3	4	5	6
1	239/25 (शेरघाटी),	32/2025–26	होण्डा मोटर साईकिल	1- JH02BB-7725 2- JC83EG0021870 3- ME4JC834MKG002115	बिन्दु यादव, पिता–अर्जुन यादव, निवासी ग्राम–झांझ, पो0– दिवनिया, थाना–बाराचट्टी, जिला–गयाजी, पिनकोड– 824201
2	272/25 (शेरघाटी)	28/2025–26	साईकिल	1- NIL 2- NIL 3- NIL	सुनील कुमार, पिता–दरोगा चौधरी, निवासी ग्राम–नावाडीह, थाना–हंटरगंज, जिला–चतरा (झारखण्ड)

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
शेरघाटी

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।
PR. No.001689 (District) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

